सम्पादक के नाम

मोदी के नाम उर्मिलेश की चिट्ठी

आदरणीय प्रधानमंत्री जी

पहली बार आपको चिट्ठी लिखने के लिए मजबूर हो रहा हूं! आशा है, अन्यथा नहीं लेंगे और उचित लगे तो इस पर विचार करेंगे!

सबसे पहले तो हम आपको बहुत विनम्रतापूर्वक सिर्फ यह याद दिलाना चाहते हैं कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं! यकीन कीजिए, भारत नामक इस बड़े देश के प्रधानमंत्री आप ही हैं!

हम आपकी तरह "इंटायर पोलिटिकल साइंस" नहीं पढ़े हैं! संघ-दीक्षित भी नहीं हैं! "हिन्दुत्व" के संस्कार, संस्कृति और धर्म-कर्म के ध्वजवाहक भी नहीं हैं! हम तो किसान-संस्कृति में पले-बढ़े! आज एक अदना सा पत्रकार हूं! किसी न्यूज चैनल या अखबार का संपादक भी नहीं हूं!

हमारी पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय और फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की है! बचपन पूर्वांचल में बीता! किसी तरह की सहानुभूति पाने के लिए हम आपकी तरह अपनी पारिवारिक-पृष्ठभूमि का हवाला नहीं देते!

इधर आपकी भाषा, आपका लहजा और आपके मुंह से उच्चरित अपशब्द किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं कि ये किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री के शब्द कैसे हो सकते हैं? बोलते वक्त, कहीं आप भी तो भूल नहीं जाते कि आप कौन हैं! यकीन कीजिए, आप यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ही भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री हैं! और जब भी आप सार्वजनिक मंच से बोलते हैं, वह भारत के प्रधानमंत्री बोलते हैं!

अभी आपने दिवंगत राजीव गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी की है! प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू पर आप और आपके दल के नेता अक्सर ही अपमानजनक टिप्पणियां करते रहते हैं!

दिवंगत राजीव आपसे बहुत पहले इस गणराज्य के प्रधानमंत्री थे! नृशंस आतंकी हमले में वह मारे गए! उनकी मां दिवंगत इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थीं। उनकी भी कट्टरपंथी-धर्मांध और सिरफिरे तत्वों ने ही हत्या की थी! श्रीमती गांधी के पिता जवाहर लाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री थे! आजादी की लड़ाई में कई साल वह जेल में रहे! उनके पिता मोतीलाल नेहरू भी आजादी की लड़ाई में लंबे समय तक जेल में रहे!

इन सबकी आप आलोचना करें, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है! पत्रकार के रूप में मैं भी इनमें कई नेताओं पर आलोचनात्मक टिप्पणियां लिख चुका हूं! कश्मीर के आधुनिक इतिहास पर मेरी एक छोटी सी किताब है, उसमें नेहरू जी की प्रशंसा और आलोचना, दोनों है!

आप नेहरू जी से नहीं मिले रहे होंगे। शायद, इंदिरा जी और राजीव जी से मिले रहे होंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही रहा! मैंने इंदिरा जी को देखा था और राजीव गांधी से मिला भी था! बातचीत भी की थी! पर आपकी तरह मैं भी जवाहरलाल नेहरू से न तो कभी मिला और न आमने-सामने कभी देखा! पर कई इतिहास ग्रंथों और स्वयं नेहरू जी की लिखी किताबों के जरिए उनसे अनेक बार मिलने का मुझे मौका मिला। लंबे समय से आप संघ और फिर भाजपा की राजनीति में सक्रिय हैं! काफी समय तक मुख्यमंत्री रहे। बहुत व्यस्त व्यक्ति हैं, इसलिए संभवत: आपको उनके बारे में या उनकी अपनी किताबें पढ़ने का मौका नहीं मिला

होगा! The Discovery of India या Glimpses of world History जैसी किताबों के जरिए आपकी अगर नेहरू जी से कभी मुलाकात हुई होती तो मोदी जी, यकीनन आपकी भाषा, आपके शब्द और आपके विचार ऐसे नहीं होते!

पहले भी आपके तेवर कुछ कम तीखे नहीं थे! पर इधर दो-तीन दिनों से आपकी भाषा मानवीय मर्यादा और राजनीतिक गरिमा की सरहदें ध्वस्त कर रही है! आपकी भाषा और आपके विचार के बारे में मुझे क्या पड़ी थी, कुछ कहने और लिखने की! लेकिन आप प्रधानमंत्री हैं और मैं एक पत्रकार! इसलिए लिखने को विवश हो रहा है! आशा है, कुपित नहीं होंगे!

सादर,

-उर्मिलेश

मनोरोगी, नमोरोगी नहीं होता लेकिन नमोरोगी के मनोरोगी हो जाने की संभावना रहेगी !

1984 को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है. 40 साल के राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं.

21 मई 1991, राजीव गांधी 46 साल के थे. और उन्हें बम से तमिलनाडु में उड़ा दिया जाता है.

2019 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए जान देने वाले 46 साल के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के लिये कहते हैं, तुम्हारा बाप भ्रष्टाचारी नंबर वन होकर मरा

आपको दुख नहीं होता ? आपको अफसोस नहीं होता ? आप इसे आम मानते हो.

मर चुके प्रधानमंत्री को लेकर इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री ऐसा बयान देता है. और उस बयान को नॉर्मल बना दिया जाता है.

दिल्ली के सीएम को कोई आवारा गाड़ी पर चढ़कर थप्पड़ मार देता है. बार-बार यही होता है. और आपको दुख नहीं होता ? अफसोस नहीं होता ?

आप उस पर चुटकले बनाते हो. हंसते हो. उनका वाला पिटा. हमारा वाला नहीं. इस देश की ये संस्कृति, ऐसे संस्कार कभी नहीं रहे। और राजनीतिक संस्कृति तो ऐसी कभी रही ही नहीं.

अटल जी ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि मैं राजीव गांधी की वजह से जिंदा हूं. नेहरू ने सार्वजनिक तौर पर अटल जी की तारीफ की। सरदार पटेल ने नेहरू को अपना नेता माना।

गांधी के कहने पर पीएम के पद के लिए चूं नहीं की। घोर आलोचक होने के बावजूद लोहिया ने नेहरू के लिए ऐसा कभी नहीं कहा.

चीन से युद्ध हारने के बाद भी संघ के नेताओं ने नेहरू को कायर कभी नहीं कहा. अब मर चुके नेहरू के लिए आपने पिछले 5 साल में क्या-क्या नहीं बोला. नेहरू की आत्मा तक को निचोड़ लिया.

तो अब राजीव का नंबर. ये कैसी राजनीतिक संस्कृति हम विकसित कर रहे हैं। और लोग हंस रहे हैं।

संवेदनशीलता नहीं दिखा सकते तो मूर्खता का प्रदर्शन तो मत करिये.

यही देश है जो इंदिरा की मौत पर बिलख रहा था. गांव-गांव में लोग मुंडन करा रहे थे. तेरहवीं कर रहे थे. यही देश है जो नेहरू की मौत के बाद पूछ रहा था अब हमारा क्या होगा ? दुनिया सवाल कर रही थी भारत बिखर जाएगा ? यही देश है जो नेहरू की मौत पर लिख रहा था- अब कौन।

यही देश है जो राजीव की मौत के बाद सुन्न हो गया था. और अब इसी देश को उनकी मौत का मजाक बनाते चुटकले फॉरवर्ड करने में शर्म नहीं आती।

मरने के बाद तो दुश्मन के लिए भी गलत शब्द नहीं निकलते। हम ऐसे कब से बन गए ? सवाल सिर्फ मोदी का नहीं है. सवाल किसी एक थप्पड़ का भी नहीं है।

सवाल हमारी अपनी संस्कृति और पहचान का है. बड़े-बड़े पत्रकार केजरीवाल को लेकर चुटकले बना रहे हैं। शर्म ह धिक्कार है. तुम्हारे ज्ञान पर। तुम्हारी सोच पर. तुम्हारे होने पर. सच कहता हूं अगली बार से ऐसा कुछ करो तो अपने घर में रखी किताबों को और अपने बुजुर्गों की यादों को आग लगा देना।

तुम ऐसा बनोगे उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा।

- साइबर नज़र

क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी आयोग बन गया है ?

चुनाव आयुक्त अशोक लवासा

2014 के बाद से चुनाव आयोग के भीतर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे भरोसा बनता नहीं है. प्रधानमंत्री को पहले भी कई तरह की रियायतें मिली हैं. वो रैली कर सकें इसलिए आयोग की प्रेस कांफ्रेंस टाली गई. लोकसभा का चुनाव लंबा किया गया. किसी किसी राज्य में एक चरण में चार सीटों पर मतदान हो रहा है. ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के नाम पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की मान्यता रदद् करने का विवाद पलट कर देखिए. दिल्ली में चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साज़िश नज़र आएगी. कितनी बहसें होती थीं उस वक्त चैनल में, जिन्हें ये करना था वो करके वापस जा चुके हैं.

चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामले आए. यह भी शर्मनाक मामला है कि भारत के प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. मोदी के खिलाफ़ 5 शिकायतें थीं. एक भी शिकायत पर पूर्ण बहुमत से क्लीनचिट नहीं मिली.

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा. इन तीनों पर भारत का हर नागरिक भरोसा व्यक्त करता है कि इनके निर्देशन में चुनाव आयोग संवैधानिक दायित्वों को निभाने में कोई समझौता नहीं करेगा. किसी भी नेता के दबाव में नहीं आएगा और न ही किसी राजनीतिक दल की मदद करेगा. चुनाव आयोग से आने वाली ख़बरें बहुत आश्वस्त नहीं कर रही हैं. सबकुछ इतिहास के भरोसे मत छोड़िए. वर्तमान का भी दायित्व है दर्ज करना. जनता तक सूचना नहीं पहुंचने दी जा रही है. इन सूचनाओं को पहुंचाइये कि चुनाव आयोग कैसे हमारे भरोसे का इम्तहान ले रहा है. हर दिन वह भरोसा पहले से अधिक हिल जा रहा है.

चुनाव आयोग के सामने प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ आचार संहिता के उल्लंघन के पांच मामले आए. यह भी शर्मनाक मामला है कि भारत के प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं. आयोग ने चेतावनी दी थी कि सेना के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. धार्मिक पहचान और उन्माद के नाम पर वोट नहीं मांगा जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के दबाव में शुरू में तीन चार नेताओं के खिलाफ़ कार्रवाई तो हुई लेकिन जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी का नाम आया तो आयोग के हाथ कांपते से लगते हैं.

9 अप्रैल को लातूर में प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा और बालाकोट के नाम पर वोट मांगा. 20 दिन लग गए फैसला लेने में. जब फैसले का वक्त आया तो दो आयुक्तों ने प्रधानमंत्री को क्लिन चिट दी. एक आयुक्त ने विरोध किया. विरोध करने वाले आयुक्त का नाम है अशोक ल्वासा. मोदी के ख़िलाफ़ 5 शिकायतें थीं. एक भी शिकायत पर पूर्ण बहुमत से क्लीनचिट नहीं मिली है. नियम तो एक ही होता है. उल्लंघन भी कोई ऐसा जटिल नहीं है मगर फैसला संदिग्ध है.

9 अप्रैल को अमित शाह ने केरल के वायनाड की तुलना पाकिस्तान से कर दी थी. अमित शाह के दिल में यही भारत है। उनसे सहमति न हो तो वे भारत के एक हिस्से को ही पाकिस्तान घोषित कर दें। इसके बाद भी चुनाव आयोग उन्हें क्लीनचिट देता है। इसे धार्मिक उन्माद और धार्मिकता का इस्तेमाल करने का आरोपी नहीं मानता है।

इन सबके बीच चुनाव आयुक्त अशोक ल्वासा भी हैं. लगातार पांच शिकायतों में वे असहमति दर्ज करते हैं. कोई आयुक्त पांच बार लगातार विरोध दर्ज करे यह सामान्य बात नहीं है। प्रधानमंत्री को जो क्लीनचिट मिल रहा है उसे आयुक्त अशोक लवासा की असहमतियों की नज़र से देखिए. आपकी रूह कांप जानी चाहिए कि क्या कोई है जो प्रधानमंत्री को बचाने के लिए वहां मौजूद है. भरोसा होना चाहिए कि कोई अशोक लवासा है जो अपने नैतिक बल पर टिका है. संवैधानिक दायित्व के बोध पर अडिग है. फिर ऐसे देखिए कि आयोग में एक के सामने दो ऐसे हैं जो लगातार प्रधानमंत्री को पांच मामलों में क्लीनचिट देते हैं. क्या चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी आयोग बन गया है?

आप किसी भी दल के समर्थक हों. इतिहास में आयोग की जो भी कहानी हो. यह काफी नहीं है. क्या हमने इस वर्तमान को इसलिए चुना है कि वह इतिहास के जैसा हो. 2014 के पहले के पूर्व चुनाव आयुक्त मुखर होकर बोलते थे. अब प्रतिक्रिया के लिए पूर्व आयुक्तों से संपर्क किया जाता है तो टाल जाते हैं. जो बोलते हैं वो भी खुलकर नहीं बोलते हैं. उनके वाक्यों को ध्यान से देखिए. क्या डर इतना बड़ा हो गया है कोई इस एक संस्था के लिए भी नहीं बोल पा रहा है? क्या आप डरने के लिए 2019 के चुनाव में हैं? क्या आप आयोग को ख़त्म होते देखने के लिए 2019 के चुनाव में हैं?